

संपादकीय

विचार के अनुरूप काम

जर्मनी अपने विचार के अनुरूप काम कर रहा है। अपने स्वयं के दूर-दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के परेशान इतिहास के साथ सार्वजनिक गणना के प्रति जर्मनी की प्रतिबद्धता ने उदार, मानवीय आदर्शों के वैश्विक नेता के रूप में इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के साथ-साथ इसकी आत्म-अवधारणा को भी आकार दिया है। परिणामस्वरूप, जर्मन धूर-दक्षिणपंथ की बढ़ती शक्ति को रोकने में स्पष्ट शक्तिहीनता जर्मन नागरिकों और नेताओं के लिए विशेष रूप से विंताजनक रही है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में, संघेधानिक अदालत ने सुदूर-दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों को निशाना बनाने में अपनी जीत का दावा किया जब उसने फैसला सुनाया कि नव-नाजी, अतिराष्ट्रवादी पार्टी, डाई हेइमत (द होमलैंड), जिसे पहले एनपीडी या नेशनलडेमोक्राटिस पार्टई डॉयचलैंड्स (एक पतली-सी पार्टी) कहा जाता था। राष्ट्रीय समाजवाद का परोक्ष संदर्भी, अपनी विचारधारा के कारण छह वर्षों तक राज्य पार्टी का वित्तपोषण प्राप्त करने में असमर्थ होगा। अदालत ने फैसला सुनाया कि पार्टी “स्वतंत्र लोकतांत्रिक बुनियादी व्यवस्था की अवहेलना करती रहती है और अपने लक्ष्यों और अपने सदस्यों और समर्थकों के व्यवहार के अनुसार, इसे खत्म करने के लिए तैयार है। नतीजा यह है कि पार्टी पर सख्ती से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि उसे फंडिंग कैसे प्राप्त हो सकती है, इस मामले में उसे गंभीर रूप से पंगु बना दिया गया है। जर्मनी में राजनीतिक दलों को सरकार में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य की वित्तीय सहायता मिलती है। वे सभी पार्टी फंडों का 50:

धोषणापत्रों पर, जिन्हें पार्टी ने कुछ साल पहले प्रकाशित किया था। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि पार्टी जिस तरह से सोचती है उसमें बहुत कम या कोई निरंतरता नहीं है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपनी स्थिति उलट दी है। अपने 1954 के धोषणापत्र में, और फिर 1971 में, जनसंघ ने 20रु1 के अनुपात को बनाए रखते हुए सभी भारतीय नागरिकों की अधिकातम आय 2,000 रुपये प्रति माह और च्यूनतम 100 रुपये तक सीमित करने का संकल्प लिया। यह इस अंतर को कम करने पर तब तक काम करता रहेगा जब तक कि यह 10रु1 तक न पहुंच जाए, जो कि आदर्श अंतर था और सभी भारतीयों को उनकी स्थिति के आधार पर केवल इस सीमा के भीतर ही आय प्राप्त हो सकती थी। इस सीमा से अधिक व्यक्तियों द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय को राज्य द्वारा "योगदान, कराधान, अनिवार्य ऋण" अपनी वेबसाइट पर, भाजपा कहती है "एकात्म मानवाद का दर्दनाक व्यक्ति को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आयाम वाले व्यक्ति के रूप में देखता है। यह आर्थिक विवाद के लिए अभिन्न दृष्टिकोण की बात करता है जिसके मूल में व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र से जुड़ा हुआ है।" इन शब्दों का क्या मतलब है? किसी सरकार और राजनीतिक दल का आध्यात्मिक आयाम से क्या लेना-देना है, और यदि यह संभव भी है तो राज्य के लिए उपलब्ध सामान्य लीवर के साथ इस आध्यात्मिक आयाम का उपयोग कैसे किया जा सकता है? ये शब्द भाजपा के धोषणापत्र में या भाजपा के बजट में कार्रवाई योग्य नीतियों के माध्यम से कैसे परिवर्तित होते हैं? यदि हैं तो वे अन्य दलों की नीतियों से किस तरह गायब हैं? आइए एक नजर डालते हैं बीजेपीजनसंघ के उन और निवेश के माध्यम से" विकास आवश्यकताओं के लिए विनियोजित किया जाएगा। पार्टी शहरों में आवासीय घरों के आकार को भी क्योंकि यह बैल और बैल को वध से बचाने की कोशिश कर रहा था। 1951 में, गोहत्या पर प्रतिबंध को "गाय को कृषि जीवन की आर्थिक कहते हैं कि "संयुक्त परिवार और अविभाज्य विवाह हिंदू समाज का आधार रहे हैं।" इस आधार को बदलने वाले कानून अंततः समाज के विघटन का कारण बनेंगे। इसलिए जनसंघ हिंदू विवाह और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को निरस्त कर देगा। जनसंघ के 1973 के जातीय हिंसा के विश्लेषण से पता चलता है कि ज्यादातर मामलों में संघर्ष हरिजनों और जातीय हिंदुओं के बीच नहीं है, बल्कि यह हरिजनों और सत्ता में मौजूद लोगों के एक समूह के बीच है, जो उंची जातियों से भी आते हैं। मतलब यह कि जाति स्वयं संघर्ष का स्रोत नहीं थी। सांस्कृतिक रूप से, पार्टी शराब के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही और देशव्यापी शराबबंदी की मांग की। और यह चाहता था कि सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का स्थान स्थानीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी द्वारा लिया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनसंघ ने कहा कि वह यूरोपी जैसे निवारक हिंसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बिना चुनौती दिए जाने दिया जा सके।

भाजपा ने दशकों से अपनी रियति की बुनियादी बातें बदल दी

और निवेश के माध्यम से” विकास आवश्यकताओं के लिए विनियोजित किया जाएगा। पार्टी शहरों में आवासीय घरों के आकार को भी क्योंकि यह बैल और बैल को वध से बचाने की कोशिश कर रहा था। 1951 में, गोहत्या पर प्रतिबंध को “गाय को कृषि जीवन की आर्थिक कहते हैं कि “संयुक्त परिवार और अविभाज्य विवाह हिंदू समाज का आधार रहे हैं।” इस आधार को बदलने वाले कानून अंततः समाज कानूनों को भी रद्द कर देगा, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत थे। यह वादा 1950 के दशक में बार-बार किया गया था।



सीमित कर देगी और 1,000 वर्ष गज से अधिक के भूखंडों के अनुमति नहीं देगी (किसी को अंबानी और अडानी को यह बताना चाहिए) 1954 में, यह कहा गया कि "ट्रैक्टर का उपयोग केवल कुंवारी मिट्टी के तोड़ने के लिए किया जाएगा सामान्य जुताई के प्रयोजनों के लिए उनके उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।" यह निःसंदेह इसलिए था

इकाई बनाने के लिए” आवश्यकीय चीज़ के रूप में समझाया गया था। 1954 में, पाठ अधिक धार्मिक था और गाय संरक्षण को “पवित्र कर्तव्य” कहा गया था। हालाँग वह कहती है कि वह आज समाज नागरिक संहिता की समर्थक पार्टी ने तलाक और एकल परिवार का लगातार विरोध किया है। इस पुराने घोषणापत्र (1957 और 1958)

कहते हैं कि "संयुक्त परिवार और अविभाज्य विवाह हिंदू समाज का आधार रहे हैं।" इस आधार को बदलने वाले कानून अंततः समाज के विघटन का कारण बनेंगे। इसलिए जनसंघ हिंदू विवाह और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को निरस्त कर देगा। जनसंघ के 1973 के जातीय हिंसा के विश्लेषण से पता चलता है कि ज्यादातर मामलों में संघर्ष हरिजनों और जातीय हिंदुओं के बीच नहीं है, बल्कि यह हरिजनों और सत्ता में मौजूद लोगों के एक समूह के बीच है, जो ऊंची जातियों से भी आते हैं। मतलब यह कि जाति स्वयं संघर्ष का स्रोत नहीं थी। सांस्कृतिक रूप से, पार्टी शराब के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही और देशव्यापी शराबबंदी की मांग की। और यह चाहता था कि सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी का स्थान स्थानीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी द्वारा लिया जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनसंघ ने कहा कि वह यूएपीए जैसे निवारक हिरासत कानूनों को भी रद्द कर देगा, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत थे। यह वादा 1950 के दशक में बार-बार किया गया था। हालाँकि, 1967 तक, इसने मांग को योग्य बनाना शुरू कर दिया और कहा कि "यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि पांचवें स्तरभकारों और विघटनकारी तत्वों को मौलिक अधिकारों का शोषण करने की अनुमति नहीं है।" समय के साथ, जनसंघ और भाजपा निवारक हिरासत के सबसे उत्साही समर्थकों में से एक बन गए। 1954 में, पार्टी ने कहा कि वह संविधान में पहले संशोधन को रद्द कर देगी जिसने "उचित प्रतिबंध" लगाकर बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था। इस संशोधन ने अनिवार्य रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया क्योंकि उचित प्रतिबंध के रूप में देखी जाने वाली सूची बहुत व्यापक और विस्तृत थी। जनसंघ ने महसूस किया कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बिना चुनौती दिए जाने दिया जा सके।

विपक्ष की रेखाएँ जो धुंधली नहीं होंगी

लोकेश
उन सभी लोगों के बीच ज
भारत में लोकतंत्र के बारे में गंभीरत
से सोचते हैं और लगातार इस बा
को लेकर चिंतित रहते हैं कि य
कैसे खद्धरे में है, इस बात व
लेकर दुख है कि कैसे विपक्षी द
भाजपा और नरेंद्र मोदी शासन के
माकेदार उदय को चुनौती देने व
लिए एक साथ नहीं रह पाए हैं
विशेषकर बिहार में नीतीश कुमार व
भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो
के बाद निराश स्पष्ट हो गई है
नीतीश के बाहर निकलने के बा
मता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा
तब अखिलेश यादव ने एकत्रप
योषणा की कि वह उत्तर प्रदेश
कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देन
वाहते हैं। अगर वह गठबंधन व
लेकर गंभीर होते तो बंद करने
इस पर चर्चा करते। इसने तीन ब
राज्यों में सहयोग को प्रभावी ढंग
खारिज कर दिया। एक अन्य ब

राज्य महाराष्ट्र में स्थिति अस्थिर है। वहां कांग्रेस के दो बड़े सहयोगी—शरद पवार और उद्धव ठाकरे—अपनी पार्टीयों के विभाजन के बाद अपने समर्थन आधार को लेकर अनिश्चित हैं। केरल में कांग्रेस की भूमिका पर वाम दलों के भीतर भी गंभीर भ्रम है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के उनके नियंत्रण से दूर जाने के बाद एकमात्र राज्य जहां से कम्युनिस्ट अपनी छाप छोड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम्युनिस्ट केरल के बायानाड में राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा को मैदान में उतार सकते हैं। दक्षिण के बाकी हिस्सों में विपक्ष तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उम्मीद लगा सकता है। कर्नाटक और तेलंगाना में उन्हें कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। इस भ्रम की स्थिति के बीच, सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने धन्यवाद प्रस्ताव में, मोदी ने विपक्षी गठबंधन के 'टूटे हुए गठबंधन' पर कटाक्ष किया।

अगस्त 2023 में, कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने कहा था कि इंडिया संगम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) से “वैचारिक रूप से अलग” था जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने पहले किया था। लेकिन उन्होंने बहुत ही संकीर्ण अर्थ में वैचारिक भिन्नता की बात कही। उन्होंने बताया कि जहां भारत एवं चुनाव-पूर्व समझौता था, वहीं यूपीए एक चुनाव-पश्चात समझौता था। जैसे-जैसे महीने बीतते गए, गठबंधन के भीतर वास्तविक वैचारिक मतभेद उजागर होते गए। कई क्षेत्रीय दलों को ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस उनके ट्रेडमार्क वैचारिक क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही है — उदाहरण के लिए, मंडल राजनीति (राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग करना)। इसकी अभिव्यक्तियों में से एक थी और संघवाद। आखिरिकार, क्षेत्रीय दलों ने अन्य पहलुओं के अलावा इन दो पहलुओं पर भी कांग्रेस की मांग पर अपनी राजनीतिक जगह बनायी।

बनाई थी। अब वे अपने अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए कांग्रेस को पुनर्जीवित नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस की आत्मसंतुष्टि और उसकी नैतिक कृपा ने सहयोगियों को और अधिक परेशान कर दिया विश्वास की कमी और ईमानदारी की कमी ने गहरी खाई पैदा की दी। पिछले मई में कर्नाटक में अपनी जीत के बाद, नवंबर में पांच अलग विधानसभाओं के लिए विधानसभा चुनाव होने तक, कांग्रेस ने गठबंधन की बातचीत और रणनीति बैठकों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह शायद गठबंधन के भीतर सीटों के लिए बेहतर सौदेबाजी की उमीद था। जब दिसंबर में नतीजे पार्टी के लिए निराशाजनक रहे, तो ऐसा नहीं लगा कि उसके पास गठबंधन कोई प्लान नहीं है। शायद कांग्रेस वह इस बात से भी डर लग रहा था कि उसके कई सहयोगियों ने खुले तौर पर इस बात की वकालत की थी कि उसे केवल उन्हीं सीटों पर लड़ाया जाए।

चाहिए, जिन पर वे हैं। 2019 में भाजपा से सीधा मुकाबला। इसका मतलब होगा लगभग 200 से अधिक सीटें। पार्टी को यह अपने सहयोगियों द्वारा अपनी राष्ट्रीय छाप को कम करने के एक अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में प्रतीत हुआ होगा। नीतीश जैसे नेताओं ने तो एक सीट पर एक विपक्षी उम्मीदवार की वकालत भी की थी। आखिरी कील राहुल गांधी की क्रॉस-कंट्री पदयात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण था। इससे सहयोगी दलों को यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस गठबंधन या चुनावी खेल को लेकर गंभीर नहीं है। उस संक्षिप्त अवधि के दौरान जब विपक्षी गठबंधन जीवित दिख रहा था, अगर लोगों ने सोचा कि वे धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए एक साथ खड़े हैं तो यह एक सरल निष्कर्ष था। विपक्ष को सकारात्मक एजेंडे से अधिक नकारात्मक एजेंडे द्वारा परिभाषित किया गया है। यह वही गलती थी जो उन्होंने 1971 में की थी, जब वे इंदिरा गांधी को बाहर करना चाहते थे दृ नारा था 'इंदिरा हटाओ। कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से इसे 'गरीबी हटाओ' कह दिया था। कुछ-कुछ ऐसा ही कार्ड मोदी ने खेला है। जितना विपक्ष ने इसे उनके 'सत्तावादी' और 'नार्सिस्टिक' गुणों के बारे में बताया है, उन्होंने तेजी से राष्ट्र, इसके सभ्यतागत आत्मसम्मान और आर्थिक गौरव का आवृत्तावान किया है। उन्होंने खुद को अतीत में देश को एक कल्पित स्वर्ण युग में वापस लाने के लिए चुने गए व्यक्ति की तरह पेश किया है। विपक्ष ने हमेशा बहिष्कार के आहार पर काम किया है जिसे वैचारिक एकता के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि किसी ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी दिखावटी बातों को गंभीरता से लिया है, तो यह बात तब उड़ गई जब अयोध्या में राम मंदिर पर उनकी प्रतिक्रिया मौन रही।

मराठा विभाजन का कष्टदायक मार्ग

सुरेश
देश ने मंगलवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में जो औपचारिक वेभाजन देखा, उसकी तैयारी लम्ब समय से चल रही थी। यह भ्रमित जातिगत पहचान, चालाक कोतण्डा, विकसित होती दलगणना, राजनीति और बढ़ती व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। यह कहा जा सकता है कि मौजूदा अतिरोध की ओर बढ़ने की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उस युग में, आरक्षण के मुद्दे ने गरीब मराठों और अमीर मराठों, मराठों और कुनबियों, मराठों और ओबीर्सों और मराठों और उच्च जातियों के वेभाजित कर दिया। जैसे हैं कैबिनेट पदों को लेकर भी सत्त्वांसंघर्ष छिड़ गया, राजनीतिक और सामाजिक कारक आपस में जुड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप और जटिलताएँ पैदा हुईं। जब मराठा

समुदाय किसी न किसी मुद्दे पर विभाजित हो गया तो यह भाजपा के लिए उपयुक्त था। इससे पहले, जब शशिकांत पवार, अन्नासाहेब पाटिल और विनायक मेटे ने आरक्षण की मांग शुरू की थी, तब भाजपा (तब जनसंघ) ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। मराठों के पक्ष में बोलने वाले चार उप-समूह थे। लेकिन जब उनके एक समूह के रूप में एकजुट होने की संभावनाएं पैदा हुईं, तो भाजपा के उच्च-जातीय आधार ने इसे प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देखा। दूसरी ओर, सामान्य तौर पर अपने समुदाय के लिए आरक्षण का समर्थन करने के बावजूद, मराठा नेताओं ने खुद हमेशा उस तरह के आरक्षण पर नजर नहीं डाली है जिससे वे खुश हैं दु शरद और अजीत पवार जैसे लोग उनके समर्थन में बहुत मुखर होने से बचते रहे हैं औ बीसी टैग के लिए जबकि मनोज

आयोग, अदालतों और मीडिया व उलझा दिया है। इन सभी ने आप की राजनीति के आलोक में पुराप्रश्न को नया आकार दिया है। तभी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं. एवं सामाजिक दृष्टि से मराठा कौन है? दो, मराठों को किस कोटे व अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए? ये दो सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को आकार देते रहे हैं. क्या ओबीसी कोटा के तहत मराठा समुदाय के दावे का कोई ऐतिहासिक आधार है? यदि मराठा की पहचान कुनबी के रूप में बदल जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि वे एक ओबीसी समूह हैं लेकिन 1950 और 1989 के बीच मराठा समुदाय ने खुद को ओबीसी समूह होने का दावा नहीं किया ओबीसी के लिए समुदाय का दावा भी कई बार खारिज किया गया है पहले काकासाहेब कालेलकर समिति

और बाद में मंडल आयोग ने मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल नहीं किया। उस समय, मराठा जाति सगठनों सहित मराठा समुदाय ने ओबीसी कोटा के तहत शामिल करने के लिए आक्रामक रूप से जोर नहीं दिया।

तो इस लिहाज से ये एक अनैतिहासिक दावा है। और पाटिल ने ओबीसी कोटा के तहत शामिल करने की मांग करते समय इस प्रारंभिक इतिहास को नजरअंदाज कर दिया है। 1990 के दशक से लेकर वर्तमान तक, विभिन्न सरकारों ने मराठों के लिए नए आरक्षण की व्यवस्था करने के प्रयास किए हैं। 2004 में सुशील कुमार शिंदे सरकार ने मराठों को ओबीसी कोटा में शामिल करने का फैसला किया। लेकिन एक अदालत ने राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। अदालतों और राज्य सरकार के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। बाद में, बापट, राणे, खत्री और मारुति गायकवाड़ आयोग ने कोटा की नई श्रेणियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सिफारिशों में एक विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) और एक सामाजिक-शैक्षिक पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) शामिल थे। इसके बजाय, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा बनाया। जबकि अदालतों ने केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस कोटा को बरकरार रखा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए एसबीसी और एसईबीसी कोटा को रद्द कर दिया गया और इन कोटा के तहत आरक्षण को अमान्य कर दिया गया। नए कोटा में राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा शामिल नहीं किया गया था दृ केवल रोजगार और शिक्षाय अदालत ने दोनों उपकरणों को भी अमान्य कर दिया।

मोदी के आत्मविश्वास से भरा आमदूनाव का गणित

ଲାଲିତ

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के समय विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों कारण हैं। प्रधानमंत्री ने सीटों का जो आकलन किया है, वह सिर्फ इस बात का संकेत है कि भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिया में नहीं पड़ता लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज भारतीय जनता पार्टी को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से ज्यादा सीटें पार करवाकर रहेगा। भाजपा इस बार चुनावों में 400 पार का नारा दे रही है। 2019 चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं। निश्चित ही इतने बड़े आंकड़े की घोषणा करने के पीछे नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक सोच, विकास की राजनीति एवं राष्ट्र-विकास का विकल रही ही, बल्कि विपक्ष में भी कुछ होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। कांग्रेस की नकारात्मक सोच, विरोध के उत्तरात्मक कारण हैं।

विपक्ष का राजनीति तो कारण है। प्रधानमंत्री ने सीटों का देश की जनता महसूस करने लगी है। कांग्रेस किस तरह नकारात्मक राजनीति का शिकार है यह कल्पना से भी बाहर था। दूसरी वजह, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा ने लोगों में एक नए जोश का संचार किया है। अंतरिम बजट में ही जिस तरह से आने वाले कुछ महीनों को लेकर नीतियों का एलान किया गया है, वह संकेत है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं चमत्कारी जीत की संभावनाओं की ओर भी वजह हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सुखद एवं उपलब्धिभरी प्रतिध्वनियां हैं, जैसे चांद एवं सूर्य पर विजय पताका फहरा देने के बाद धरती को स्वर्ग बनाने की मुहीम चल रही है। राष्ट्रीय जीवन में विकास की नयी गांधां लिखते हां भास्त्र को बनाने की जनता नरेन्द्र मोदी ने आंकड़ों के बावजूद देख रहा हूं कि देश का मिजाज भारतीय जनता पार्टी को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से ज्यादा सीटें पार करवाकर रहेगा। भाजपा इस बार चुनावों में 400 पार का नारा दे रही है। 2019 चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं। निश्चित ही इतने बड़े आंकड़े की घोषणा करने के पीछे नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक सोच, विकास की राजनीति एवं राष्ट्र-विकास का विकल रही ही, बल्कि विपक्ष में भी कुछ होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। कांग्रेस की नकारात्मक सोच, विरोध के उत्तरात्मक कारण हैं।

विपक्ष का राजनीति तो कारण है। प्रधानमंत्री ने सीटों का देश की जनता महसूस करने लगी है। कांग्रेस किस तरह नकारात्मक राजनीति का शिकार है यह कल्पना से भी बाहर था। दूसरी वजह, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा ने लोगों में एक नए जोश का संचार किया है। अंतरिम बजट में ही जिस तरह से आने वाले कुछ महीनों को लेकर नीतियों का एलान किया गया है, वह संकेत है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं चमत्कारी जीत की संभावनाओं की ओर भी वजह हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सुखद एवं उपलब्धिभरी प्रतिध्वनियां हैं, जैसे चांद एवं सूर्य पर विजय पताका फहरा देने के बाद धरती को स्वर्ग बनाने की मुहीम चल रही है। भाजपा इसलिए भी आशान्वित है, क्योंकि जिस विपक्षी एकता की जनता 2023 के मध्य से चल रही है, राष्ट्रीय जीवन में विकास की नयी गांधां लिखते हां भास्त्र को बनाने की ओर आंकड़ों के बावजूद देख रहा हूं कि देश का मिजाज भारतीय जनता पार्टी को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से ज्यादा सीटें पार करवाकर रहेगा। भाजपा इस बार चुनावों में 400 पार का नारा दे रही है। 2019 चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं। निश्चित ही इतने बड़े आंकड़े की घोषणा करने के पीछे नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक सोच, विकास की राजनीति एवं राष्ट्र-विकास का विकल रही ही, बल्कि विपक्ष में भी कुछ होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। कांग्रेस की नकारात्मक सोच, विरोध के उत्तरात्मक कारण हैं।

विपक्ष का राजनीति तो कारण है। प्रधानमंत्री ने सीटों का देश की जनता महसूस करने लगी है। कांग्रेस किस तरह नकारात्मक राजनीति का शिकार है यह कल्पना से भी बाहर था। दूसरी वजह, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा ने लोगों में एक नए जोश का संचार किया है। अंतरिम बजट में ही जिस तरह से आने वाले कुछ महीनों को लेकर नीतियों का एलान किया गया है, वह संकेत है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं चमत्कारी जीत की संभावनाओं की ओर भी वजह हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सुखद एवं उपलब्धिभरी प्रतिध्वनियां हैं, जैसे चांद एवं सूर्य पर विजय पताका फहरा देने के बाद धरती को स्वर्ग बनाने की मुहीम चल रही है। भाजपा इसलिए भी आशान्वित है, क्योंकि जिस विपक्षी एकता की जनता 2023 के मध्य से चल रही है, राष्ट्रीय जीवन में विकास की नयी गांधां लिखते हां भास्त्र को बनाने की ओर आंकड़ों के बावजूद देख रहा हूं कि देश का मिजाज भारतीय जनता पार्टी को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 से ज्यादा सीटें पार करवाकर रहेगा। भाजपा इस बार चुनावों में 400 पार का नारा दे रही है। 2019 चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं। निश्चित ही इतने बड़े आंकड़े की घोषणा करने के पीछे नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक सोच, विकास की राजनीति एवं राष्ट्र-विकास का विकल रही ही, बल्कि विपक्ष में भी कुछ होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। कांग्रेस की नकारात्मक सोच, विरोध के उत्तरात्मक कारण हैं।

में भाजपा की शानदार जीत दर्ज करना भी है। विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का परिणाम तो कल्पना से भी बाहर था। दूसरी वजह, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा ने लोगों में एक नए जोश का संचार किया है। अंतर्रिम बजट में ही जिस तरह से आने वाले कुछ महीनों को लेकर नीतियों का एलान किया गया है, वह संकेत है कि भाजपा अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक एवं चमत्कारी जीत की संभावनाओं की ओर भी वजह हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सुखद एवं उपलब्धिभरी प्रतिध्वनियां हैं, जैसे चांद एवं सूर्य पर विजय पताका फहरा देने के बाद धरती को स्वर्ग बनाने की मुहीम चल रही है, राष्ट्रीय जीवन में विकास की नयी गाँधारां ल्युग्नते द्वा भाजपा को

थी, उसमें दरारो पड़ती ही जा रही है। तमाम विपक्षी पार्टी यह अपने—अपने ढंग से चुनाव लड़ाकों को तैयार हैं और कांग्रेस से उनके खीचतान चल रही है।

फिर, जहां

जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं, वह पार्टी ने अपने अनवरत प्रयासों द्वारा खुद को मजबूत बना लिया। फिर चाहे वह महाराष्ट्र हो या बिहार कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के पारंपरागत भाजपा एवं मोदी विरोध का कोई सशक्त धरातल एवं मुद्दे नहीं हैं। वैसे तो हर एक का जीवन अनेक विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरा रहता है। लेकिन कांग्रेस का हर दिन कई विरोधाभासों के बीच बीच रहा है। कांग्रेस की उल्टी गिनति चल रही है। उसकी उल्टी गिनति तो लम्बी चलेगी। परं जनता दिमाग में एक बात गढ़ते तक है।



बेरोजगारी की चर्चा सुनने को मिलती है, जबकि 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट केवल 12 लाख करोड़ के अमापात्म था। शीते 2014 के पहले डिजिटल इकोनॉमी का साइज ना के बराबर था। आज भारत, दुनिया की अग्रणी डिजिटल दृकोन्तंत्री है।

